

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

06.08.2019

उपतहसीलदार छानीबड़ी द्वारा अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति भादरा के पत्रांक 2831 दिनांक 31.08.18 के विरुद्ध निगरानी पेश करते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने एक अपील इस आशय से पेश कि ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो ख०न० 90 तादादी 0.885 व ख०न० 91 की 0.101 हैक्ट० भूमि गैरमूमकिन जोहड़ व पाल दर्ज है जिसमें 1000 वर्गफुट पर बलवीर पुत्र हरिसिंह जाति मेघवाल ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, तथा उसने अपने अतिक्रमण वाली जगह पर अप्रार्थी स० 1 व 3 ने अप्रार्थी स० 2 के साथ साजबाज कर पटटे बलवीर पुत्र हरिसिंह के नाम पटटा न० 0 दिनांक 05.01.97 तादादी 12.5 गुणा 30 जारी करवा लिया है। अप्रार्थी स० 2 ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में पटटा जारी करने का अधिकार है। परन्तु अप्रार्थी स० 1 व 3 ने तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी से दुरभिसंधि करके राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की गरज से ग्राम छानीबड़ी के रोही मौजा चक 5 सीएचएन जो ख०न० ख०न० 90 तादादी 0.885 व ख०न० 91 की 0.101 हैक्ट० भूमि गैरमूमकिन जोहड़ व पाल जिसमें 1000 वर्गफुट जो राज्य सरकार की सम्पति है, जो आबादी भूमि से अलग है, जो रिकार्ड में गै०मु० जोहड़ व पाल दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा विधि विरुद्ध किये गये अतिक्रमण के लिए प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक 21.11.14 को अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है। तथाकथित पटटे के आधार पर अपने अतिक्रमण को पुख्ता करने के लिए निर्माण कर रहे हैं तथा सरकारी कार्य में भी बाधा डाल रहे हैं, इसलिए उक्त पटटे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जावे। उक्त पटटा को विधि विरुद्ध होने व पटटा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद होने से अपील अधिनस्थ न्यायालय में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत पेश की गई परन्तु अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा द्वारा मात्र एक पत्रांक के आधार पर अपील मुल ही उचित कार्यवाही हेतु वापिस लोटा दी गई व लिखा गया की अपील राज० पंचायती राज० अधिनियम 1996 की धारा 61(1) के तहत समय अवधि 30 दिन से अधिक होने से स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिससे व्यथित होकर निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत कि जा रही है—

क - यह है कि अप्रार्थीगण स० 1 के पक्ष में ग्राम छानीबड़ी की रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. के ख०न० 90 तादादी 0.885 व ख०न० 91 की 0.101 हैक्ट० भूमि गैरमूमकिन जोहड़ व पाल जिसमें 1000 वर्गफुट में अप्रार्थी स० 1 व 3 ने अप्रार्थी स० 2 के साथ साजबाज कर पटटे बलवीर पुत्र हरिसिंह जाति मेघवाल छानीबड़ी के नाम पटटा न० 0 दिनांक 05.01.97 तादादी 12.5 गुणा 30 फुट जारी करवा लिया है। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पटटे जो की रिकार्ड में गै०मु० जोहड़ व पाल दर्ज है का पटटा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई थी एवं मातहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाकर मुल ही पत्रावली वापिस लौटाई गई है। एवं उपरोक्त निर्णय विधिक अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है।

यह है कि अप्रार्थी के पक्ष में जारी पटटा ग्राम पंचायत छानीबड़ी द्वारा पाल की भूमि पर जारी किये हैं न कि आबादी भूमि पर जारी किये हैं जो

अपास्तनीय है।

ग- यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ नियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया एवं मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाकर पत्रावली लौटा दी गई जो कतई नियम विरुद्ध एवं बिना विश्लेषण के निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर निगरानी अधीन निर्णय दिनांक 31.08.18 पत्रांक 2831/2018 अनवानी स्टेट बनाम नरेश आदि निरस्त फरमाया जावे एवं पट्टा दिनांक 05.01.97 को निरस्त फरमाया जावे।


निगरानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी की तलबी कि गई अप्रार्थी स0 1 की तामील स्वयं पर व अप्रार्थी स0 3 की तामील पुत्रवधु पर होनी पाई जाती है, परन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं इनके उपस्थित नहीं आने के कारण इनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है।

राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार छानीबड़ी की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होंने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी स्वीकार कर प्रसंगत पट्टा निरस्त करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 5 सीएचएन सम्बत 2073-2076 खाता स0 189/181 मु0न0/ख0न0 90 की 0.885 व मु0न0/ख0न0 91 खाता स0 182/174 की 0.101 हैक्ट भूमि की किस्म गैर मुमकिन पाल दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट(पीआईएल) स0 1554/04 निर्णय दिनांक 12.01.17 अनवान गुलाब कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी. सिविल रिट स0 1536/03 निर्णय दिनांक 02.08.2004 अनवानी अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि नदी नाला, वन विभाग एवं कैचमेंट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। चुकि हस्तगत निगरानी में जो आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं वह जोहड़ की भूमि की पायतन(पाल) पर जारी किये गये हैं। ऐसे विधि विरुद्ध पट्टों को उक्त न्यायिक दृष्टांतो व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हस्तगत पट्टा दिनांक 05.01.97 जो बलवीरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति चमार साकिन छानीबड़ी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.01.97 को जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार भादरा, नायब तहसीलदार छानीबड़ी व विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा व सरपंच ग्राम पंचायत छानीबड़ी को भेजी जावे। पत्रावली फौसला सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया।


(अशोक असीजा)
अतिरिक्त जिल्ह कलक्टर
मोहर (हनुमानगढ़)